सबसे (₹) बड़ा रुपया

'कुशाग्र'

...त ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत विभिन्न पहलूओं पर भारत की रैंकिंग में आया बदलाव

...ameters	2018 report (2017)*	2019 report (2018)*
...ia's rank ...t of 190)	100	77
...aling with ...struction permits	181	52
...ding across borders	146	80
...rting a business	156	137
...tting credit	29	22
...tting electricity	29	24
...forcing contracts	164	163
...ying taxes	119	121
...otecting minority ...estors	4	7
...solving insolvency	103	108
...gistering property	154	166

...e : *Year in bracket represents the year report was published

Source: World Bank Doing Business2019 Report

लिये की गयी है जबकि व्यवहार में हम देखें तो पायेंगे कि वही क्षेत्र अनेक तरह की बीमारियों से पीड़ित है और जी.एस.टी., जिसे सबसे बड़ा आर्थिक सुधार सरकार ने बतलाया था, बाद तो उसकी कमर ही टूटने की स्थिति बनने लगी है। इसका मतलब यह है कि हमारे लिये जो तकलीफ है वस्तुत: वही सामने वाले के लिये खुश खबरी का घोतक इसलिये है कि उसी से उसके कारोबार के विस्तार होने के अवसर बढ़ेंगे।

बतलाया है जिसका आशय भी यही है कि जितनी स्पीड से कारोबार के **अन्तिम संस्कार** के परिवेश का विस्तार होगा उतने ही अधिक अवसर सामने वाले के लिये भविष्य में सृजित होंगे और एन.पी.ए. की समस्या से लड़ते-लड़ते सिस्टम अपने आप थककर वह सब निर्णय तेजी से करेगा जो इसकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिये किये जाने चाहिये।

आज की बात का सार यह है कि जब कोई बाहरी एजेंसी आपके किये गये साहसिक निर्णयों के लिये पीठ थपथपाते हुए जो भाव प्रदर्शित करती है तो उसका अर्थ आपको क्या समझना चाहिये, गति प्रधान रूपैये के काल में आपकी समझ के लिये एक नयी चुनौती बनती चली जाती है भले ही सरकार एवं नीति निर्माता इसे कैसे भी माने और उपयोग करें। नयी रैंकिंग में हमारा देश 2017 में 100वें से बढ़कर 77वें स्थान पर आ गया है और इस बढ़ोतरी में Construction Permit, Trading Across Borders, Getting Credit आदि मामलों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है (आलेख के बीच ग्राफ देखें) पर समझने की बात यह है कि हमारी सरकारों के निर्णयों का आधार अब लोकल से ग्लोबल बनता जा रहा है जो कि इस गति प्रधान रूपैये की महरबानी की देन है, अत: हम शनै:शनै: यह देखेंगे कि अर्थ शब्द पर आश्रित हर निर्णय में दो **अर्थ** समाहित होंगे पर सबका मंतव्य यही होगा कि कौन किसको पूंजी से गरीब बनाते हुए ऐसे परिवेश का विस्तार कर सकता है जिसका By- Product हो कि **बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रूपैया।**

(For Old Series Contact At info@nafanuksan.com)

For suggestion/feed back contact jskothari@nafanuksan.com

...ता जागरूकता सप्ताह ...ग्राम सभा का आयोजन

...ं नये भारत का निर्माण की थीम पर ...ा की गई। - का.सं.

कारोबार सुगमता रैंकिंग

अगले तीन साल में शीर्ष 25 में पहुंचना महत्वपूर्ण

नयी दिल्ली। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जतायी कि भारत अगले तीन साल में कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों की सूची में स्थान बना सकता है। विश्व बैंक द्वारा बुधवार को जारी कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत ने पिछले साल के मुकाबले 23 पायदान की ऊंची छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में भारत अब 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इस उल्लेखनीय बढ़त पर कांत ने कहा कि भारत अगले साल शीर्ष 50 देशों में आ सकता है।

दिल्ली में एक कार्यक्रम से इतर कांत ने कहा कि यह प्रदर्शन (रैंकिंग में उछाल) शानदार है... इस आकार और विविधता वाले किसी अन्य देश ने तीन साल में 65 पायदान की छलांग नहीं लगायी है... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच साल में शीर्ष 50 देशों में शामिल होने का सपना देखा था। अगले तीन साल में शीर्ष 25 स्थान हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पिछले साल विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 100वें स्थान पर रहा था। - पीटीआई

वया...

का सबसे पुराना और बड़ा कार्यक्रम है। जीएसपी को विभिन्न देशों से आने वाले हजारों उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये डिजाइन किया गया है। जिन उत्पादों की शुल्क मुक्त आयात की रियायत रद्द की गयी है, उनमें भारत के कम से कम 50 उत्पाद है। 2017 में जीएसपी के भारत का अमेरिका को शुल्क मुक्त निर्यात 5.6 अरब डॉलर से अधिक रहा। - पीटीआई

रेलवे...

कि खाद्यान्न, आटा, दालों, उर्वरक, नमक और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। किसानों और आम आदमी को ध्यान में रखते हुये सीमेंट, डीजल सहित पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। कंटेनर ढुलाई शुल्क को पांच प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जबकि अन्य लघु सामानों की ढुलाई दरें भी 8.75 प्रतिशत बढ़ा दी गई। - पीटीआई

जीएसटी...

का 13 प्रतिशत और महाराष्ट्र का 11 प्रतिशत है। इस साल अप्रैल में पहली बार जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 1,03,458 करोड़ रुपये पर पहुंचा था। उसके बाद से यह लगातार 90,000 करोड़ रुपये के ऊपर बना हुआ है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में हर माह एक लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा है। मई में जीएसटी संग्रह 94,016 करोड़ रुपये, जून में 95,610 करोड़ रुपये, जुलाई में 96,483 करोड़ रुपये, अगस्त में 93,960 करोड़ रुपये और सितंबर में 94,442 करोड़ रुपये रहा था। अक्टूबर के कुल जीएसटी संग्रह में केन्द्रीय जीएसटी 16,464 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 22,826 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 53,419 करोड़ रुपये रहा। - पीटीआई

जुलाई...

और केरल जैसे प्रमुख बाजार के बाढ़ से प्रभावित होने जैसे कई कारणों के चलते इस तिमाही में सोने की मांग पर असर पड़ा।'' साल की आखिरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) आम तौर पर सोने की मांग के लिए अच्छी रहती है। त्यौहारों और शादियों के चलते इस दौरान सोने की मांग और खरीद बढ़ती है। सोमसुंदरम ने कहा कि इसके बावजूद हालांकि इस साल सोने की मांग इस दौरान सामान्य ही रह सकती है, क्योंकि बाजार तरलता की कमी है, वहीं भारत में इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में चुनाव के चलते इसकी आवाजाही भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा सालभर में सोने की मांग कम रहने का अनुमान है। यह 700 से 800 टन के दायरे में रह सकती है। रपट में कहा गया है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में इस साल आभूषणों की कुल मांग 10 प्रतिशत बढ़कर 148.8 टन है जो पिछले साल समान अवधि में 134.8 टन थी। मूल्य के आधार पर आभूषण की मांग में वृद्धि 14 प्रतिशत रही है। यह 40,690 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल की इसी अवधि में 35,610 करोड़ रुपये थी। इसी दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्वर्ण भंडार 13.7 टन बढ़ाया है। इससे उसका कुल स्वर्ण भंडार 21.8 टन हो गया। स्वर्ण क्षेत्र में निवेश मांग भी इस अवधि में 11 प्रतिशत बढ़ी और यह 34.4 टन रही। जबकि 2017 की तीसरी तिमाही में यह 31 टन थी। - पीटीआई

बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

(पूर्व में बीएफएल डवलपर्स के रूप में जाने है)

पंजीकृत कार्यालय : 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर- 302006, फोन : 9214018877

E. : bfldevelopers@gmail.com, W.: www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 13 नवम्बर, 2018 मंगलवार को सायं 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 1, तारानगर, अजमेर रोड, जयपुर- 302006 में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ उसी तारीख के रूप में सम्पत्तियों व देनदारियों के स्टेटमेन्ट पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और लेखा परीक्षण जांच के लिए रिकॉर्ड में लाया जायेगा। पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bflfin.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
सीएस सुरभि रावत
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 1 नवम्बर, 2018
स्थान : जयपुर